संसद के समक्ष अभिभाषण – 23 फरवरी 1984

लोक सभा	-	सातवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	ज्ञानी जैल सिंह
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री एम. हिदायतुल्लाह
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

मुझे वर्ष 1984 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उसको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

चालू वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था में भारी सुधार हुआ है, जिससे व्यापक रूप से वर्षा न होने के कारण हुई हानि को पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष कृषि उत्पादन में 9 प्रतिशत वृद्धि की आशा है, जबकि पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत की कमी हुई थी। अनाज का उत्पादन 1420 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से अधिक हो जाने की आशा है, जबकि 1982-83 में वास्तविक उत्पादन 1284 लाख मीट्रिक टन था और इससे पहले सबसे अधिक उत्पादन का रिकार्ड 1333 लाख मीट्रिक टन रहा था। कृषि उत्पादन में ये सफलताएं वर्षों से अपनाई गई हमारी ठोस नीतियों और कार्यक्रमों का ही परिणाम है। 1982-83 में सिंचाई क्षमता में 23.4 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई थी। अब 1983-84 में इसमें 23.7 लाख हेक्टेयर की और वृद्धि होने की सम्भावना है। सिंचाई में जो क्षमता हासिल की गई है उसके उपयोग में सुधार लाने के लिए खासतौर से कोशिशें की जा रही हैं। अधिक पैदावार देने वाली फसलों की किस्मों के कार्यक्रमों में विस्तार किया जाता रहा है और यह उम्मीद है कि 1983-84 में 520 लाख हेक्टेयर भूमि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगी। 1983-84 के दौरान उर्वरक की खपत योजना लक्ष्य से काफी अधिक हो जाएगी।

सूखी भूमि पर खेती की तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए 4246 लघु-जल विभाजकों का पता लगाया गया है। इससे गरीब से गरीब ग्रामीण समुदायों को सहायता मिलेगी। 1983-84 में छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए केन्द्रीय रूप में चलाई गई एक योजना शुरू की गई थी।

औद्योगिक अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने और बुनियादी ढांचे में सुधार का काम पूरी गति से चलता रहा। कोयले के उत्पादन में सितम्बर के बाद लगातार सुधार हुआ है और 1983-84 के दौरान इसका उत्पादन 1400 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंच जाएगा। 1983-84 के पहले 9 महीनों के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वर्ष से लगभग 5 प्रतिशत बढ़ गया है। खनिज तेल का उत्पादन जो 1980-81 में 105 लाख मीट्रिक टन था और 1982-83 में 210.6 लाख मीट्रिक टन हो गया था, अब 1983-84 में बढ़कर उसके 260 लाख मीट्रिक टन हो जाने की सम्भावना है। रेल द्वारा माल की ढुलाई को पिछले वर्ष से ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के लिए विशेष कोशिशें की गई हैं। बन्दरगाहों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और 1983-84 में मुख्य बन्दरगाहों पर जो कुल यातायात होने की सम्भावना है, उम्मीद है कि वह दस सौ दस लाख मीट्रिक टन से अधिक होगा, यह अब तक का सबसे अधिक यातायात होगा।

औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति जो वर्ष के पहले छह महीनों में धीमी रही थी, उसमें वर्ष के आखिरी छह महीनों में सुधार हुआ है और 1983-84 में कुल औद्योगिक विकास दर 4.5 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है। औद्योगिक निर्माण क्षेत्र में अच्छा उत्पादन रहा है। सूती कपड़ा इंजीनियरी और सीमेंट उद्योगों में भारी सुधार हुआ है।

देश के विभिन्न भागों में मुख्तलिफ दबावों के बावजूद वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंधों की स्थिति भी सन्तोषजनक बनी रही। आर्थिक विकास में गति को बनाए रखने के सरकार के अनुरोध का आम कामगारों पर अच्छा असर पड़ा है, जिसका पता उत्पादन में हुई वृद्धि से चल जाता है।

इस वर्ष कुल राष्ट्रीय उत्पादन की विकास दर लगभग 6 से 7 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है, जबकि 1982-83 में यह दर केवल 1.8 प्रतिशत थी। छठी योजना की पहले चार वर्षों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन की औसत विकास दर 5.4 प्रतिशत हो जाएगी। इस उपलब्धि पर देश जायज तौर पर गर्व कर सकता है।

कीमतों की स्थिति हमारे लिए चिन्ता का कारण रही है। 7 जनवरी, 1984 को मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 10.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव का अधिक कारण, सूखे की वजह से 1982-83 में कृषि उत्पादन में कमी, रहा था। इस दबावों का मुकाबला करने और मुद्रा के फैलाव को कम करने के लिए अनेक उपाए किए गए हैं, जिनमें खाद्यान्नों, तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विस्तार और उसे मजबूत बनाया जाना, अनाज की वसूली का जोरदार अभियान, आयात के जरिए समय पर घरेलू पूर्तियों का

सीमान्त विस्तार, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और मुद्रा प्रणाली में अधिक नकदी को घटाने के उद्देश्य से राजकोष और मुद्रा पर अंकुश लगाना शामिल है। 1983–84 की रिकॉर्ड फसल और बुनियादी ढांचे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार सुधार से आने वाले महीनों में मुद्रा के फैलाव की दर को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार ने खर्च को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही उत्पादन और उसकी कुशलता तथा क्षमता के पूरे उपयोग की प्रेरणा को भी बनाए रखा है।

हमारे विदेशी भुगतान की स्थिति में सुधार हुआ है। व्यापार अन्तराल लगातार दूसरे वर्ष में घट जाने की सम्भावना है। अप्रैल–अक्तूबर, 1983 के दौरान (तेल को छोड़कर) निर्यात में 1982–83 की इसी अवधि की तुलना में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयातों का मूल्य (तेल निर्यात के अलावा) 2.5 प्रतिशत गिर गया। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमताओं के निर्माण और आयात की अधिक मात्रा को कम करने की नीति से लाभ हुआ है। एक दूसरी उत्साहजनक बात यह है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों से धन की प्राप्ति में काफी सुधार हुआ है।

चूंकि हमारी सुरक्षित विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है, इसलिए सरकार ने स्वेच्छा से ही यह निर्णय किया है कि वह चालू वर्ष के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ एक्स्टेंडेड फंड फेसेलिटी के अधीन कोई और अधिक धन नहीं लेगी। कुल 5 बिलियन एसडीआर में से हम केवल 3.9 बिलियन का ही उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार 1.1 बिलियन एसडीआर का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दूसरे विकासशील देशों की सहायता के लिए उपलब्ध हो गया है। हमारे देश के लोग विदेशी तालमेल की हमारी नीतियों की कामयाबी पर गर्व कर सकते हैं।

20–सूत्री कार्यक्रम को, जिसमें निर्धनता को दूर करने के उपायों पर जोर दिया गया है, जोरदार ढंग से लागू किए जाने से गांव के निर्धन लोगों की दशा में सुधार हो रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन 90 लाख ग्रामीण परिवारों को जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 32 लाख परिवार भी शामिल हैं, छठी योजना के पहले तीन वर्षों में सहायता दी गई है। पहले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर कुल मिलाकर 2253 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। चालू वर्ष में और भी 30 लाख परिवारों की सहायता की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन और अधिक रोजगार पैदा करने के लक्ष्यों को, योजना के पहले तीन वर्षों में पूरी तरह हासिल कर लिया गया और चालू वर्ष में भी इस दिशा में प्रगति संतोषजनक है। 15 अगस्त, 1983 को एक नया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं। तालीमयाफ़ता बेरोजगारों को अपना रोजगार खुद चुनने के नए कार्यक्रम को भारी सफलता मिली है। 1983–84 के लिए 2.5 लाख शिक्षित व्यक्तियों की सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

माननीय संसद सदस्यगण, 1983–84 में भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों से वाकिफ हैं। 17 अप्रैल, 1983 को रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया गया था। इनसेट–1बी को 30 अगस्त, 1983 को सफलता के साथ छोड़ा गया था, जो 15 अक्तूबर, 1983 से हमारे दूरसंचार, दूरदर्शन, रेडियो और मौसम विज्ञान कार्यक्रमों में सहायता दे रहा है। दूरदर्शन सेवाओं में भारी विस्तार की योजना बनाई गई है, जिससे कि इसकी सेवाओं के अंतर्गत 1983–84 में 23 प्रतिशत जनसंख्या से बढ़कर 1984–85 तक 70 प्रतिशत जनसंख्या आ सके। भारत ने दक्षिणी ध्रुव संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इस प्रकार इसका 15वां सलाहकार सदस्य राज्य बन गया है। अब तक दक्षिणी ध्रुव के तीन अभियान आयोजित किए गए हैं और वहां एक नियमित स्टेशन भी स्थापित किया जा चुका है। सबसे पहली बार दो महिला वैज्ञानिक उस महाद्वीप में गई हैं। हमने केन्द्रीय हिन्द महासागर में बहु धातु पिंड के व्यापक सर्वेक्षण हेतु एक मार्गदर्शक क्षेत्र के लिए अपने आपको अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के पास रजिस्टर्ड करा लिया है। मद्रास परमाणु बिजली केन्द्र की पहली इकाई, 2 जुलाई, 1983 को बनकर तैयार हो गई, इसका ढांचा और डिजाइन स्वदेश में ही तैयार किया गया था। यह अब 200 मेगावाट तक बिजली तैयार कर रही है।

संसद ने हाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्वास्थ्य की देख–रेख के निरोधात्मक, प्रेरक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं पर जोर दिया गया है। इस नीति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें समाज को शामिल किया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये दूर–दराज के देहाती इलाकों के लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तपेदिक, कुष्ठ रोग और अन्धेपन पर नियंत्रण पाने के लिए भारी उपाय किए जा रहे हैं। परिवार नियोजन में भारत की कोशिशों को उस समय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल हुई, जब हमारी प्रधान मंत्री को न्यूयार्क में 30 सितम्बर, 1983 को हुए एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र संघ का जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। गर्भधारण के प्रति 25.9 प्रतिशत दम्पत्तियों को सुरक्षित किया गया है और यह प्रतिशत अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। परिवार नियोजन की मुख्तलिफ विधियों को अपनाने वालों की संख्या अप्रैल–दिसम्बर, 1983 में पिछले वर्ष की इसी अवधि से 15 प्रतिशत बढ़ गई है।

शिक्षा में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा को जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, सब तक पहुंचाने और 1990 तक प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को खत्म करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहा। रेडियो और टेलीविजन की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा के एक जबरदस्त कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी यह कोशिश रही है कि विश्वविद्यालयों और उच्च टेक्नोलॉजी की संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए। शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए गठित दो आयोगों का कार्य प्रगति पर है।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कला परिषद् की स्थापना की गई है, जो देश के सांस्कृतिक विकास और देश की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए मुख्तलिफ क्षेत्रों में की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों में सुधार लाने के लिए नीतियां तैयार करेगी। हमारे पुस्तक उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् की भी स्थापना की गई है।

देश एकता और अखण्डता के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए दृढ़ इरादे और सद्भावना के वातावरण में ही लगातार तरक्की कर सकता है। साम्प्रदायिक और पृथकतावादी तत्वों की विघटनकारी गतिविधियों, हिंसात्मक आन्दोलनों और अनेक क्षेत्रों में हुई राष्ट्र की उपलब्धियों को मिट्टी में मिलाने की योजनाबद्ध कोशिशों से जो नुकसान पहुंचा है, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ये प्रवृत्तियां राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रही हैं। कुछ अन्दरूनी और बाहरी ताकतें भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को कमजोर करने के काम में लगी हुई हैं।

आज की जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक और राजनीतिक आजादी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सतर्कता पर ज्यादा ध्यान दें। हर एक देशभक्त नागरिक को चाहिए कि वह ऐसी ताकतों को कुचलने में सरकार के साथ सहयोग करे जो जाति, नस्ल, क्षेत्र या भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करती हैं। हाल ही में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधारा के मतभेद को भुलाकर एक मत से यह स्वीकार किया गया था कि राष्ट्रीय एकता के ढांचे को मजबूत किया जाए और भारतीयता की भावना को बढ़ावा दिया जाए। यह निर्णय बहुत ही उत्साहजनक था। आन्दोलनों के समर्थन में हिंसा का सहारा लेने और धार्मिक स्थानों पर असामाजिक तत्वों को शरण देने के विरुद्ध लगभग सभी पार्टियों में सहमति है। अपराधियों द्वारा पूजा स्थलों का इस्तेमाल किए जाने से धर्म के नाम पर धब्बा तो लगता ही है साथ ही उनकी पवित्रता भी नष्ट होती है और राष्ट्र हितों को नुकसान पहुंचता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बढ़ते हुए इस अहसास को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में तबदील करें जिससे कि देश में विभिन्न दलों और मुख्तलिफ वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय एकता के एक मजबूत सूत्र में बांधा जा सके।

असम में राज्य सरकार ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारी प्रयास किए हैं। इन कोशिशों को जनता का व्यापक समर्थन मिला है, जिसने यह महसूस किया है कि हिंसा से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक गड़बड़ी ही फैलती है। अधिकरणों ने विदेशियों के मसले पर एक संकल्प तैयार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अवैध रूप से देश में दाखिल होने वालों पर निगरानी रखने के लिए भी कड़े उपाय किए गए हैं। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्यगण समझौते और मेल-मिलाप की प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

पंजाब में मासूम लोगों के खिलाफ दर्दनाक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। कुछ ताकतों ने सम्प्रदायों के बीच सदियों पुराने भाईचारे के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिशें की हैं। परन्तु यह देखकर भारी सन्तोष होता है कि अधिकांश लोग चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, नफरत के दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार से गुमराह नहीं हुए हैं। यह जरूरी है कि उस राज्य में फिर से शांति और सामान्य स्थिति कायम की जाए। सरकार हमेशा ही इस बात की फिक्र में रही है कि पंजाब की समस्याओं को सभी संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के जरिए हल किया जाए।

हाल ही में, हरियाणा में साम्प्रदायिक हिंसा का फैलना एक दुखदायी घटना है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभावित इलाकों में जल्दी ही फिर से शांति स्थापित हो जाएगी।

साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियों में जो तेजी हुई है, वह सरकार के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय रही है। इनसे देश की सुरक्षा और अखण्डता के लिए खतरा है। एक ऐसे आतंकवादी गिरोह द्वारा जिसका यह दावा है कि वह जम्मू व कश्मीर में पृथकतावादी आन्दोलन की नुमाइन्दगी करता है, ब्रिटेन में एक भारतीय राजनयिक की कायरतापूर्ण हत्या किए जाने से हमारे लिए इस बात की जरूरत बढ़ गई है कि हम सतर्क और चौकस रहें। ऐसी घटनाओं के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हमारी राजनीतिक प्रणाली इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए काफी मजबूत और लचकदार है हमारी लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थिति मजबूत है। भारत के लोगों ने बार-बार अपने इस दृढ़ निश्चय का सबूत दिया है कि हम बड़ी मुश्किलों से हासिल की गई अपनी आजादी और एकता की रक्षा कर सकते हैं। यह हमारा काम है कि हम उनकी इस असीम शक्ति और आदर्श का उपयोग राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए करें।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति शांतिजनक नहीं है। शस्त्रों की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है और शस्त्रों पर सारे विश्व में 600 बिलियन डालर वार्षिक से ज्यादा खर्च हो रहा है। नि:शस्त्रीकरण की बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इंटरमीडिएट न्यूक्लीयर फोर्सेस को सीमित करने के संबंध में बातचीत स्थगित हो गई है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आशाएं भी इसी प्रकार से कमजोर पड़ गई हैं।

हमारे अपने क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण खराब हो गया है। हिन्द महासागर क्षेत्र का लगातार सैनिकीकरण होता जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में अति आधुनिक शस्त्रों के आ जाने से चिंता पैदा होती है। हम अपने दुर्लभ साधनों का इस्तेमाल विकास के कामों में करना पसंद करते हैं, परन्तु हम अपनी रक्षा जरूरतों के प्रति भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। हमारे चारों ओर इस प्रकार की तैयारी के बावजूद, हमने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की अपनी नीति को कायम

रखा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सरकार हमारे विरुद्ध किए जा रहे प्रचार को बंद करने के लिए दोस्ती, शांति और सहयोग के लिए हमारे प्रस्तावों और बेहतर संबंधों के लिए कदम उठाए और इस प्रकार की हमारी इच्छा का सकारात्मक रूप से उत्तर दे। श्रीलंका में जातीय हिंसा से जिसमें भारतीय नागरिक और तमिल तथा भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति भारी संख्या में हताहत हुए थे और सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ था, सारे देश को स्वाभाविक रूप से गहरी चिन्ता हुई। यह सन्तोष की बात है कि श्रीलंका सरकार ने हमारी सद्भावनापूर्ण कोशिशों के प्रस्ताव को मान लिया है, जिससे कि किसी व्यावहारिक राजनीतिक समझौते में सुविधा हो। हम उम्मीद करते हैं कि सर्वदलीय सम्मेलन से कोई मुश्तकिल और संतोषजनक हल निकल आएगा। चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सीमा प्रश्न के समझौते के उद्देश्य से कोशिशें की जा रही हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ अनेक बार यात्राओं का आदान-प्रदान और आपसी विचार-विमर्श हुआ है, जिससे कि प्रमुख समस्याओं का हल निकाला जा सके और आपसी संबंधों में और सुधार लाया जा सके। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का सम्मिलित कार्यक्रम शुरू किया जाना इस दिशा में एक लाभदायक कदम था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में हमें भूटान नरेश का स्वागत करने का अवसर मिला था।

नई दिल्ली में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों का 7वां सम्मेलन 1983 की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस सम्मेलन ने फिर से इस बात की पुष्टि की है कि गुटनिरपेक्ष नीति लगातार संगतिपूर्ण और उचित है। इस आन्दोलन की अध्यक्ष होने के नाते, प्रधानमंत्री ने शांति, नि:शस्त्रीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में पहले से ही अनेक प्रारम्भिक कदम उठाये हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहल यह थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयार्क में अनौपचारिक रूप से शिखर स्तर पर विचार-विमर्श किए गए। इन विचार-विमर्शों का भारी स्वागत हुआ है और इन्हें आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत को उपयोगी प्रक्रिया में सहायक माना है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के भीतर हुई घटनाओं के संबंध में मंत्रिस्तर पर गुटनिरपेक्ष देशों के दल का पश्चिम एशिया में भेजा जाना भी इस दिशा में एक कदम था। सरकार फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और दक्षिणी अफ्रीका तथा नामीबिया में मुक्ति आन्दोलनों को हर मुमकिन सहायता देने के लिए सैद्धांतिक नीति के रूप में दृढ़ता से पाबन्द है। हमने नवम्बर में राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की थी। इससे औद्योगिक और विकासशील देशों के शासनाध्यक्षों को साथ-साथ मिलने का मौका मिला और शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हल को नया समर्थन मिला।

सोवियत संघ और समाजवादी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग की परम्परा बढ़ती जा रही है हमें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोवियत संघ के राष्ट्रपति, श्री यूरी आन्द्रोपोव के निधन पर गहरा दु:ख हुआ है। प्रधानमंत्री सोवियत जनता के दु:ख में भारत की हमदर्दी प्रकट करने के लिए मास्को गई थीं। वहां सोवियत

संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव श्री कान्स्टेंटिन चर्निनको के साथ उनकी उपयोगी बैठक हुई थी, जिसमें आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की इच्छा को दोहराया गया।

प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में राष्ट्रपति रीगन के साथ उपयोगी विचार-विनिमय किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में "भारत उत्सव" मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। पश्चिम यूरोप के देशों के साथ हमारे संबंध दोनों ओर से की गई उच्च स्तर की अनेक यात्राओं से और भी मजबूत हुए थे।

मैंने चेकोस्लोवाकिया, कतर और बहरीन की राजकीय यात्राएं की थीं। प्रधानमंत्री ने युगोस्लाविया, फिनलैंड, डेनमार्क, नार्वे, आस्ट्रिया, साईप्रस और ग्रीस की यात्राएं की थीं। वे पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मिली थीं। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष सम्मेलन के अवसर पर राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शामिल होने के अलावा, हमने अनेक प्रतिष्ठित विदेशी मेहमानों की भी मेजबानी की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष सम्मेलन के शुरू होने के अवसर पर भारत की राजकीय यात्रा की थी। बुल्गारिया के राष्ट्रपति, जर्मनी संघीय गणराज्य के चान्सलर, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति और चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हमारे देश में तशरीफ लाने वाले दूसरे विशिष्ट मेहमान थे। इन यात्राओं से भारत और इन देशों के बीच सहयोग और दोस्ती के संबंधों को मजबूत बनाने में सहायता मिली है।

माननीय सदस्यगण, हमारा गणराज्य तनाव के दौर से गुजर रहा है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कामों के लिए देश के लोक सेवकों और जनता के नुमाइन्दों की दृढ़ निष्ठा की जरूरत है। जितना हम राष्ट्र से लेते हैं उससे ज्यादा हमें उसे देना चाहिए। आज हमारे लिए राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति पुनः समर्पण की भावना की जरूरत है, ताकि हम सभी राष्ट्रीय एकता और विकास में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

मैं कामना करता हूं कि माननीय सदस्यों को अपने उन कठिन कार्यों में जो उनके सामने हैं, सफलता हासिल हो।

जय हिन्द।